

शाला चयन मानदंड एवं बच्चों के भविष्य के प्रति अभिभावकों की प्रत्याशा का विश्लेषण

डॉ. रचिता श्रीवास्तव

शा.वि.या.ता.स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छ.ग.

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 13 March 2019

Keywords

शाला चयन मानदंड, अभिभावकों की प्रत्याशा

Corresponding Author

Email: srachita[at]yahoo.com

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध के माध्यम से बच्चों के लिए शाला चयन करने हेतु अभिभावकों के मानदंड एवं बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी की जाने वाली प्रत्याशा को जानने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई-दुर्ग क्षेत्र से 220 अभिभावकों का चयन न्यायदर्श के रूप में किया गया है, जिसमें 110 अभिभावक मध्यम सामाजिक-आर्थिक परिवार से एवं 110 अभिभावक निम्न सामाजिक-आर्थिक परिवार से सम्बन्धित हैं। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। मध्यम सामाजिक-आर्थिक अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता को महत्व देते हैं। निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले अभिभावक फीस संरचना एवं घर से शाला की दूरी को ज्यादा महत्व देते हैं।

भूमिका:

हमारे देश की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद सरकारी स्कूल हैं। देश के सभी वर्गों को शिक्षा देने के लिए ये स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की दर में आई कमी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। छत्तीसगढ़ देश का 28 वां राज्य है। यहाँ कि औसत साक्षरता 70.28%, (ग्रामीण 66.76 % और शहरी 84.79 %) है। परन्तु निपा एवं एम.एच. आर.डी. (2013) के अनुसार राज्य का एडुकेशन डवलपमेंट इंडेक्स (EDI) विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के मामले में बहुत ही खराब है। सरकारी विद्यालयों की यह तस्वीर सुखद तो नहीं कही जा सकती।

यदि हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो अभिभावकों के पास बहुत सारे विकल्प होते जहाँ वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दी सकते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः सरकारी स्कूल ही होते हैं। जब प्राथमिक स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश करना होता है तो किसी भी अभिभावक के लिए बहुत ही कश्मकश की स्थिति होती है। प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्कूल किसी भी बच्चों के भविष्य के आधार होते हैं। अतः प्रस्तुत शोध के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए शाला चयन करने हेतु अभिभावकों के मानदंड एवं उनकी प्रत्याशा को जानने का प्रयास किया गया है।

पूर्व अध्ययन :

प्यारेलाल राघवन (2015) ने एच.बी.सी के अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर बताया कि भारतीय अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा एवं करियर के प्रति बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। अध्ययन के अनुसार 51 प्रतिशत अभिभावक बच्चों का अच्छा करियर चाहते हैं, 49 अभिभावक बच्चों की खुशहाल जिंदगी को वरीयता देते हैं। 33 प्रतिशत अभिभावक बच्चों के स्वस्थ जीवन शैली को महत्व देते हैं जबकि विकसित देशों के अभिभावक बच्चों की करियर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। भारत में अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनीयर बनाना चाहते हैं जबकि चाइना के माता-पिता ने इंजीनीयर को कम पसन्द किया। भारत में 88 प्रतिशत अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा स्नातकोत्तर पूर्ण करे जबकि यू.एस. में 31 प्रतिशत चाहते हैं कि उनका बच्चा स्नातकोत्तर पूर्ण करे।

स्टाफ रिपोर्टर (2017) एसोसोचेम के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 60 प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाकर खुश हैं। उनके अनुसार प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत ज्यादा है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त क्रियाएँ भी ज्यादा करवाते हैं। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक की तुलना में ज्यादा संतुष्ट थे।

सुमीर कर्माकर (2017) ने कैग की रिपोर्ट 2016, के हवाले से बताया कि आसाम में 2011 से 2016 के बीच सरकारी

स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस अवधि में प्राइवेट स्कूलों में नामांकन गोथ 114 प्रतिशत था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 238 निम्न प्राथमिक स्कूल और 15 उच्च प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां किसी भी बच्चों का नामांकन नहीं हुआ।

साहा देवानिक (2017) ने गीता गांधी किंगडॉन के शोध पत्र से यह जानकारी दी कि पांच वर्षों के दौरान, सरकारी स्कूलों में औसत नामांकन प्रति स्कूल 122 से गिरकर 108 हुआ है। जबकि निजी स्कूलों में यह 202 से बढ़कर 208 हो गया है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 के बीच भारत के 20 राज्यों के सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या में 1.3 करोड़ की कमी हुई है जबकि निजी स्कूलों ने 1.75 करोड़ नए छात्रों का नामांकन हुआ है। यह जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है, जो भारत के सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। डीआईएसई डेटा के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि सरकारी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के माता-पिता का मानना है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। गांधी के अनुसार छात्रों के घर की पृष्ठभूमि के कई मूल्यांकन संकेत देते हैं कि निजी स्कूलों में बच्चों के सीखने का स्तर खराब नहीं है और सरकारी स्कूलों की तुलना में अध्ययन बेहतर है।

सम्पादकीय टीम, नईदुनिया (2017) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तीसरी के सिर्फ 22 प्रतिशत बच्चे ही दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ पाते हैं। शिक्षा के स्तर की देशव्यापी पड़ताल करने वाली एजेंसी असर (एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट) की वर्ष 2016 की ताजा रिपोर्ट बुधवार को जारी हुई है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के तीसरी के बच्चे अक्षर को समझकर पढ़ने में पहले से होशियार हो गए हैं। रिपोर्ट में यह संकेत है कि अब बच्चों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ रहा है। 2011 में प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों का नामांकन प्रतिशत 12 था, जो अब बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।

उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. माता-पिता द्वारा अपने बच्चों से की जाने वाली प्रत्याशाओं का अध्ययन करना।
2. माता-पिता की प्रत्याशाओं पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. बच्चों के प्राथमिक शिक्षा हेतु माता-पिता द्वारा की जाने वाली शाला चयन मानदंड का अध्ययन करना।

4. माता-पिता द्वारा की जाने वाली शाला चयन मानदंड पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध सर्वे विधि पर आधारित है।

न्यायदर्श : शोध में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई-दुर्ग क्षेत्र से 220 अभिभावकों का चयन न्यायदर्श के रूप में किया गया है। न्यायदर्श में 110 अभिभावक मध्यम सामाजिक – आर्थिक परिवार से एवं 110 अभिभावक निम्न सामाजिक – आर्थिक परिवार से सम्बन्धित है।

शोध –उपकरण:

माता-पिता की प्रत्याशाओं एवं उनके द्वारा अपने बच्चों के लिए की जाने वाली शाला के चयन मानदंड को जानने के लिए वरीयता चेक लिस्ट का उपयोग किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण :

माता-पिता की बच्चों से प्रत्याशाएं :

माता-पिता द्वारा अपने बच्चों से की जाने वाली अपेक्षाओं को जानने के लिए वरीयता चेक लिस्ट में अपनी अपेक्षा के अनुरूप वरीयता देने को कहा गया। वरीयता चेक लिस्ट के अवलोकन करने से पाता चलता है कि अभिभावक अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधन, सरकारी अधिकारी, चिकित्सा, शिक्षक, पुलिस आदि क्षेत्रों को भी अभिभावकों ने पसन्द किया।

माता-पिता की प्रत्याशाओं पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव :

माता-पिता की प्रत्याशाओं पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव देखा गया।

निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले 45 % माता-पिता आई.टी.आई. में अपने बच्चे का भविष्य देख रहे तो मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले 48 % माता-पिता एन आई टी. और आई.आई.टी. जैसे संस्थानों में अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं।

माता-पिता द्वारा की जाने वाली शाला चयन मानदंड:

बच्चों की शिक्षा हेतु माता-पिता निम्नलिखित प्रमुख मानदंड को ध्यान में रखते हुए शाला चयन का चयन करते हैं:

1. अंग्रेजी माध्यम

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 2. शिक्षा की गुणवत्ता | 6. शाला का माहौल |
| 3. फीस संरचना | 7. साथी-समूह |
| 4. अधोसंरचना | 8. स्कूल बस सुविधा |
| 5. घर से शाला की दूरी | 9. ब्रांड |

शाला चयन मानदंड पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव:

तालिका -01: शाला चयन मानदंड

क्रमांक	मानदंड	मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति	निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति
1	अंग्रेजी माध्यम	100%	20%
2	शिक्षा की गुणवत्ता	89%	25%
3	फीस संरचना	50%	95%
4	अधोसंरचना	75%	60%
5	घर से शाला की दूरी	5%	90%
6	शाला का माहौल	60%	15%
7	साथीसमूह-	12%	50%
8	स्कूल बस सुविधा	70%	10%
9	ब्रांड	40%	00%
10	नेतृत्व	00%	00%

माता-पिता द्वारा की जाने वाली शाला चयन मानदंड पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति का प्रभाव तालिका में परिलक्षित है। उपरोक्त तालिका के अनुसार मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले अभिभावकों के लिए शिक्षा का माध्यम बहुत ही प्रभावी मानदंड है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढाना चाहते हैं। जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले अभिभावक फीस संरचना एवं घर से शाला की दूरी को ज्यादा महत्व देते हैं। साथी-समूह मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले अभिभावकों के लिए विशेष मायने नहीं रखता जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले 50% अभिभावक इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्रांड के सम्बन्ध में 40% मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वर्ग के अभिभावक महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले इसे कोई तजब्बू नहीं देते। अपने बच्चों से उच्च प्रत्याशा रखने वाले अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही रुख करते हैं। जबकि निम्न प्रत्याशा रखने वाले अभिभावक के लिए माध्यम का विशेष महत्व नहीं होता। सरकारी स्कूलों में वे अपने बच्चों का दाखिला करा कर खुश हैं।

निष्कर्ष:

1. अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेजना चाहते हैं।
2. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता आई.टी. आई. में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं।
3. मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले माता-पिता एन आई टी. और आई.आई.टी जैसे संस्थानों में अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं।
4. अभिभावक अंग्रेजी माध्यम, शिक्षा की गुणवत्ता, फीस संरचना एवं अधोसंरचना को शाला चयन का प्रमुख कारण मानते हैं।
5. मध्यम सामाजिक-आर्थिक अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढाना चाहते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता को महत्व देते हैं।
6. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले अभिभावक फीस संरचना एवं घर से शाला की दूरी को ज्यादा महत्व देते हैं।

सन्दर्भ:

1. देवानिक साहा (2017) 5 वर्षों में निजी स्कूलों में 1.7 करोड़ छात्रों का इजाफा, सरकारी स्कूलों में 1.3 करोड़ छात्रों का नुकसान , इंडियास्पैड, April 24, 2017. <http://www.indiaspendhindi.com>
2. Jaiswal Anuja (2013). Chhattisgarh among bottom 10 in education development, TOI, Jul 19, 2013. <https://timesofindia.indiatimes.com>
3. Karmakar Sumir (2017). Parents prefer private to govt schools: Study , The Telegraph, Tuesday , March 14 , 2017. <https://www.telegraphindia.com>
4. Raghavan Pyralal (2015). Indian parents have very high expectations about their children's education and careers, July 15, 2015. <https://blogs.timesofindia.indiatimes.com>
5. सम्पादकीय टीम, नईदुनिया (2017). दो साल में हिन्दी में 7, गणित में 5 प्रतिशत बढ़ा बच्चों का शिक्षा स्तर, नईदुनिया , 19 Jan 2017. <https://naidunia.jagran.com>
6. Staff Reporter (2017). 60% of parents happy to send kids to govt schools: survey, The Hindu , New Delhi, October 05, 2017, <http://www.thehindu.com>